

एफ नं: 116/15/2017-सीएक्स-3

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 10" जनवरी, 2019

प्रति

प्रधान मुख्य आयुक्त / सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त (चंडीगढ़, मेरठ, कोलकाता और शिलांग क्षेत्र) महानिदेशक, जीएसटीआई।

विषय: सिक्किम सहित जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित पात्र औद्योगिक इकाइयों को बजटीय सहायता योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण।

मैडम /सर,

बजटीय सहायता योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए दिनांक 23.05.2018 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), व्यापार संघों और क्षेत्र संरचनाओं द्वारा अग्रेषित विभिन्न तकनीकी और परिचालन मुद्दों पर भी चर्चा की गई और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को विचारार्थ भेजा गया। योजना में संशोधन की आवश्यकता वाले मुद्दों को डीआईपीपी द्वारा योजना में संशोधन की अधिसूचना जारी करने के माध्यम से संबोधित करने का प्रस्ताव है। इस परिपत्र को जारी करने के माध्यम से जो मुद्दे परिचालन और प्रकृति में स्पष्ट हैं, उन्हें संबोधित किया जाता है।

उन इकाइयों की पात्रता जो थ्रेशोल्ड छूट या विनिर्माण छूट वाले सामान के तहत थीं, लेकिन जीएसटी शासन के तहत जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है: पूर्ववर्ती शासन के तहत, ऐसी इकाइयों को लाभ उपलब्ध कराया जाता था यदि बाद की तारीख में उत्पाद शुल्क लगाया जाता था।

2. योजना शेष अवधि के लिए पात्र इकाइयों को लाभ प्रदान करने का प्रयास करती है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था के तहत जारी पूर्ववर्ती छूट अधिसूचनाओं के तहत छूट प्राप्त कर रहे थे। ऐसे में ऐसी इकाइयों को लाभ नहीं मिलेगा।

किट ए के एक हिस्से के रूप में आपूर्ति के लिए इनपुट की खरीद सौंदर्य प्रसाधन निर्माता ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या उसके हेयर कलर किट को निर्माण माना जाएगा। किट में बट्टी में अपने कारखाने में निर्मित रंगीन ट्यूब और क्षेत्र आधारित छूट वाले स्थानों में स्थित तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित अन्य वस्तुएं शामिल हैं और किट का हिस्सा बनने के लिए खरीदी जाती हैं। यह तैयार हेयर कलर किट उनके कारखाने द्वारा साफ किया जाता है।

3. जब तक तीसरे पक्ष से प्राप्त माल किट के लिए इनपुट की प्रकृति का है, जिसके संबंध में कुछ सामान स्वयं निर्मित किया जा रहा है, किट को एक ऐसा उत्पाद माना जाएगा जिसकी आपूर्ति की जा रही है। किट के लिए लाभ तब तक उपलब्ध होगा जब तक स्रोत उत्पाद इनपुट/सहायक उपकरण की प्रकृति के होते हैं और ऐसे सामानों के लिए सामान्य व्यापार भाषा में किट के रूप में आपूर्ति की जाती है।

एक ही जीएसटीएन के तहत कई व्यावसायिक परिसर और धनवापसी की राशि का निर्धारण: व्यापार ने दर्शाया है कि जहां सभी लेनदेन के लिए एकल रिटर्न होने के कारण राज्य में संस्थाएं कई संचालन कर रही हैं, वहां एक का क्रेडिट ऑफसेट हो जाता है अन्य और उनके द्वारा भुगतान की गई नकद राशि से अधिक बजटीय सहायता की अनुमति नहीं दी जा रही है।

4. योजना के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाण पत्र का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा, एक निर्धारिती के पास एक अद्वितीय GSTIN वाले एक अलग व्यवसाय वर्टिकल के रूप में पात्र इकाई के अलावा अपने संचालन को पंजीकृत करने का विकल्प भी होता है। इस संबंध में अधिसूचित होने की तिथि से सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के संदर्भ में व्यवसाय वर्टिकल की परिभाषा को छोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसलिए उक्त अधिनियम के संचालन के बाद पात्र इकाई अपने मौजूदा जीएसटीआईएन को बनाए रख सकती है और अन्य कार्यों के लिए अलग से जीएसटीआईएन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह का लाभ बजटीय सहायता की योजना के अनुसार तिमाही शुरू होने के 1 दिन से उपलब्ध होना चाहिए।

मामले जहां स्वीकृति प्राधिकारी का निष्कर्ष निरीक्षण दल से भिन्न होता है: योजना में कोई प्रावधान नहीं है कि यदि स्वीकृति प्राधिकारी निरीक्षण दल के निष्कर्षों से भिन्न होता है तो किसके विचार प्रबल होंगे।

5. निरीक्षण दल और स्वीकृति प्राधिकारी के अधिदेश अलग-अलग हैं। निरीक्षण दल को इकाई की पात्रता तय करनी होती है जबकि स्वीकृति प्राधिकारी धनवापसी के दावे की पुष्टि और मात्रा निर्धारित करता है। ऐसे मामलों में जहां डीआईपीपी टीम द्वारा निरीक्षण से पहले रिफंड की मंजूरी दी गई है, ऐसे दावे अनंतिम हैं। जहां इनमें से कोई भी इकाई निरीक्षण के आधार पर पात्र नहीं पाई जाती है

रिपोर्ट, वापसी राशि योजना में प्रदान किए गए तरीके से वसूल की जा सकती है।

मुख्य आयुक्त (शिलांग) द्वारा रिफंड दावे के सत्यापन में कठिनाई के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था। प्रक्रिया के अनुसार, जीएसटी के तहत एक निर्धारित मासिक रिटर्न फाइल करता है जबकि रिफंड आवेदन तिमाही के लिए होता है।

6. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि वापसी आवेदन के साथ संलग्न तालिका में माहवार विवरण संलग्न किया जाए। यह धनवापसी दावों के त्वरित और अधिक सटीक सत्यापन को सक्षम करेगा।

पात्र इकाइयों द्वारा दायर दावों के निपटान की समय सीमा पर चर्चा की गई क्योंकि वर्तमान में कोई समय सीमा नहीं है यह निर्णय लिया गया कि दावों का निपटान 2 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए क्योंकि आवेदक ने पहले ही देनदारी का भुगतान किया है और कर का भुगतान किया है और किसी भी मामले में, यह 30 दिनों के बाद का नहीं होना चाहिए। क्षेत्राधिकार मुख्य आयुक्त को इसकी निगरानी करनी है और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है।

स्वीकृति आदेश के पीएओ द्वारा स्याही हस्ताक्षरित प्रति पर जोर देने से धनवापसी की स्वीकृति में देरी होती है। यह सुझाव दिया गया था कि डीसी/एसी द्वारा पीएओ को मंजूरी आदेश की स्याही हस्ताक्षरित प्रति की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां आयोग की दरें दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं।

8. यह स्पष्ट किया गया कि मैनुअल मोड में इसकी आवश्यकता है। हालांकि, ऑटोमेशन के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद ऑटोमेटेड मोड में, मंजूरी आदेश पर स्याही से हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

अपील का प्रावधान: यदि इकाई स्वीकृति प्राधिकारी/निरीक्षण दल के निष्कर्षों से असंतुष्ट है तो इकाई के लिए अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

9. योजना के तहत सहायता अनुदान की प्रकृति में है और कराधान कानून के तहत शुल्क की वापसी नहीं है। अतः किसी अपीलीय फोरम की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होता है।

बहु-स्थान निर्धारिती के संबंध में सत्यापन: 'व्यापार के प्रमुख स्थान' पर अधिकार क्षेत्र वाले डीसी \ एसी द्वारा पात्र इकाई को बजटीय सहायता स्वीकृत की जानी है। कुछ मामलों में पात्र इकाई का स्थान और इकाई का प्रमुख स्थान भिन्न होता है। यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि दोनों में से कौन सा अधिकारी दावों का सत्यापन करेगा।

10. जीएसटी व्यवस्था के तहत अपनाई जा रही प्रणाली यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी और 'व्यापार के प्रमुख स्थान' पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले केंद्रीय कर अधिकारी धनवापसी के दावे को मंजूरी देंगे। ऐसा अधिकारी राज्य में किसी अन्य स्थान पर स्थित पात्र इकाई के संबंध में क्षेत्राधिकारी अधिकारी है जैसा कि जीएसटी कानून के अनुसार स्थिति है। एक ही पंजीकरण संख्या के तहत कवर किए गए बहु-स्थानीय निर्धारिती का सत्यापन करते समय, क्षेत्राधिकार वाले एसी/डीसी अन्य लोगों से इनपुट ले सकते हैं।

क्षेत्राधिकार, जहां आवश्यक हो।

यह बताया गया कि फील्ड अधिकारियों द्वारा दावे के सत्यापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तक पहुंच नहीं है। इससे सत्यापन में परेशानी हो रही है।

11. फील्ड अधिकारियों के पास वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर तक पहुंच है।

स्वीकृत बजटीय सहायता राशि के लिए पूर्व-लेखापरीक्षा या लेखा-परीक्षा के बाद की आवश्यकता के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है।

12.1. चूंकि ऐसे भुगतानों की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय द्वारा की जाएगी, तदनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह दोहराया जाता है कि ये भुगतान टैक्स रिफंड नहीं बल्कि बजटीय समर्थन हैं।

12.2 स्पष्टीकरण से दायर संरचनाओं द्वारा योजना के कार्यान्वयन में स्पष्टता और एकरूपता लाने की उम्मीद है। कार्यान्वयन में अनुभव की गई कठिनाई, यदि कोई हो, को बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

माजिद खान
(ओएसडी-सीएक्स)